

Harijans have been allowed to be re-elected by the party in power? (Time Bell rings) Here is a Government which is doing lip service or paying lip sympathy to the members of the Harijan community. It is only in words. When it comes to actual facts and reality, it is otherwise. This is a Government which is interested in pulling down the Harijans and depriving the Harijans of their rights they got and the powers they got under the leadership of Babasaheb Dr. Ambedkar, who was one of the eminent architects of our Constitution. Sir, I am really sorry that a petty legislation like this is being brought. (Time Bell rings). It has a petty intention I oppose this Bill, Sir. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Now, if the House desires—there are only two minutes more—we shall take up the 6 o'clock agenda, if the House so desires. Otherwise I am prepared to allow Dr. Adise-shiah to...

DR. MALCOLM S. ADISE-SHIAH (Nominated): I will speak only for two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): That is all right. Please go ahead. (Interruptions).

DR. MALCOLM S. ADISE-SHIAH: Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Central Silk Board (Amendment) Bill, with the request that the Minister clarify the points raised by Mr. Hegde and Mr. Madhavan. I did not read this Bill as being aimed at removing a person, whoever that person may be, from the position of presidentship. I read this Bill as having a simple purpose. When the original 1948 Act was passed, there was an *ex-officio* Chairman as I understand it. The Commerce Minister was the *ex-officio* Chairman, Pt. Jawaharlal

Nehru was at one time Commerce Minister and Chairman of the Silk Board. And then after the Commerce Minister it was the Textile Commissioner. When this *ex-officio* went, a rule was made which Mr. Hegde referred to, providing for three-year membership. Now, the only question I would like to ask the Minister is, why are you moving the rule into the Bill? I think you are filling avoid here by doing this. I think you should answer Mr. Madhavan's question.

6 P.M.

The only other point I would like to make is that the job before the Silk Board is a very big one. There is no doubt that the production of silk yarn has now increased since Independence, since 1951, six-fold. We are now producing 5000 million tonnes of silk yarn. But we are also importing about 1000 million tonnes from China, if I am not mistaken. I think the main task of the Board is to develop this industry so that we stop importing. We should also try to stabilise our prices because the internal price of silk yarn is higher than the price of imported yarn and the price keeps fluctuating which is a great blow to the grower and the weaver.

Finally, I hope that the position of the Silk Board will be more and more reflected by the parties which are involved in this industry.

Thank you, very much.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION
on points arising out of the answer given on 9th March, 1982, to starred question 23, regarding customs clearance for import of drug intermediates under OGL

श्री लाडली मोहन निराम (मध्य प्रदेश):
उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की जो सब से दुखती रग है उस की तरफ मैं मंत्री जी का

ध्यान आज आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बीमारी इनसान की सब से बड़ी मजबूरी है। और उपाध्यक्ष महोदय, चाहे वह कोई भी इनसान हो जो बीमारी से मुनाफा कमाये उस में और कोठे पर बैठने वालों में कोई फर्क नहीं होता—वह भी किसी की मजबूरी से पैसा कमाते हैं। आज हालत यह हो गयी है कि हिन्दुस्तान में व्याधियों का आयात जो 63-64 में करीब-करीब 13-14 करोड़ रुपये का था अब बढ़ते-छूटते शैतान की आत की तरह करीब-करीब 900 करोड़ रुपये का हो गया है। इसमें करीब-करीब 64 विदेशी कम्पनियाँ हैं। कुछ देशी कम्पनी भी बाहर से माल मंगाती हैं, लेकिन ये 64 विदेशी कम्पनियाँ ही हैं जिन का एकछत्र अधिकार है।

एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है और उसी चीज को महेनजर रखते हुए सरकार ने अपने उद्योग कायम किये। जो मेरी सूचना है उसके अनुसार आज करीब 4 उद्योग हैं जो सरकार के हैं। हैरत यह है कि आजादी से पहले जन भावनाओं में प्रेरित हो कर डा० बिधान चन्द्र जैसे लोगों ने, जिन की राष्ट्रीयता पर कोई शक नहीं कर सकता, वह दुनिया के नम्बर एक के आदमी थे, विदेशी दवाओं के मामले में, विदेशी ज्ञान के मामले में इस दृष्टि को महेनजर रखते हुए कि भारत की बीमारियाँ भारत की ही दवाओं से और भारत की ही कम्पनियों द्वारा उत्पादित दवाओं से ठीक की जाय ग्लूकोट नाम की कम्पनी बनायी। मैं बहुत समय से मरीजी से इस पर पत्र-व्यवहार करता रहा। यह एक राष्ट्रीय कम्पनी है, उस के पीछे राष्ट्रीयता का एक बहुत बड़ा मानस है। उस को महेनजर रखते हुए इस कम्पनी को सरकार को अपने ताबे में लेना चाहिए। यही कम्पनी है जो कि जीवनदायनी औषधियाँ बनाती है, उस पर इसका सर्वाधिकार है, लेकिन विदेशी कम्पनियों की साजिस से पता नहीं क्या

घोटाला हुआ कि आज इस ग्लूकोट कम्पनी को उन जीवनदायनी औषधियों बनाने से रोक कर इन औषधियों को विदेशी कम्पनियों को दे दिया गया है। अब अगर ऐसा हुआ है—जो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हुआ है—तो मुझे सरकार की नीयत पर शक करने का हक है। वैसे मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदय, आप को शायद यह भी ताज्जुब होगा कि हिन्दुस्तान में देशी-विदेशी मिलाकर करीब 5 हजार कम्पनियाँ हैं। इन में से बहुत सी छोटी हैं जो स्थानीय स्तर पर अपना काम करती हैं। इन का उत्पादन भी सीमित है लेकिन वे कम्पनियाँ 15 हजार दवाइयाँ बना रही हैं। मंत्री महोदय, मैं आभारी हूँगा आप सदन के अन्दर कहने की हिम्मत करे और ईमानदाराना तरीके से हिम्मत करें—आपकी ही सरकार के द्वारा स्थापित समिति जिस को हाथी कमेटी कहते हैं—हाथी के समान वह मोटी थी, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि उस की जो सिफारिशें थी उन का क्या हुआ।

हाथी कमेटी ने अपने सुझावों में कहा था कि हिन्दुस्तान में 90 प्रतिशत बीमारियाँ केवल 44 दवाओं के जरिये ही दूर की जा सकती हैं। उनका एक सुझाव यह था कि जितने ब्रैंड नेम हैं जिन पर सर्वाधिकार है विदेशी कम्पनियों को उन को खत्म कर देना चाहिए। 117 ब्रैंड नेम आज भी चलते हैं जिन पर उनका एकाधिकार है और वह ब्रैंड नेम ऐसे नहीं हैं कि जो जीवनदायनी औषधियों से जुड़े हुए हैं। आज हालत तो यह है कि जब से हिन्दुस्तान में इन विदेशी कम्पनियों का अधिपत्य बढ़ा है और बीमारियों की तादाद बढ़ी है तो उन बीमारियों के लिये जो आवश्यक औषधियाँ हैं उन की तरफ इन कम्पनियों के द्वारा उतना ध्यान नहीं दिया जाता,

[श्री लाडली मोहन निगम]

वे दवाइयां चाहे देशी हों या विदेशी हों, जितना कि शक्ति वर्धक गोलियों की तरफ या तरह तरह के आकर्षक विज्ञापन आदि दे कर लोगों को लुभाने के लिये नयी नयी दवाइयां निकालने के लिये उनके द्वारा प्रयत्न किया जाता है और आज हिन्दुस्तान के डाक्टर एक तरह से इन कम्पनियों के दलाल हो गये हैं। इन कम्पनियों के जब प्रतिनिधि आते हैं तो वह इन डाक्टरों को अपना लिटरेचर या सेपिल दे जाते हैं और उन के आधार पर ही वे दवाइयां लिखते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि हिन्दुस्तान में दवाइयों के लिये बुनियादी खोज ही खत्म हो गयी है, जब कि हिन्दुस्तान दुनिया का एक अकेला देश है ऐसा कि जिस के पास सब तरह का फ्लोरा और फाँना है, जड़ी बूटियां हैं और उन बीमारियों की दवाइयों के साथ, उन को बनाने के लिये जो आवश्यक हैं, पेड़ हैं, और वे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों नहीं घोषणा करती कि हिन्दुस्तान में अगर कोई जीवनदायिनी दवाइयां हैं और यदि उन को बाहर से मंगाने की जरूरत पड़ती है तो उन का उपयोग सिर्फ सरकारी कारखानों में ही होगा और इस प्रकार केवल सरकारी कारखाने ही जीवनदायिनी औषधियां बनायेंगे। इस तरह के चार कारखाने हैं हिन्दुस्तान में ऐंटीबायोटिक, आई० डी० पी० ल० ग्लूकोनेट और एक और है जिमकानाम में भूल रहा हूं, यह चार कारखाने ही इस प्रकार की औषधियां ही बनायेंगे। इस दवाइयों के आयात में जो घोटाला चल रहा है उसको रोकने का एक ही तरीका है क्योंकि इन मगरमच्छों से आप पार नहीं पा सकते। मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हाथी

कमेटी की रिपोर्ट के बाद और जब यह साबित हो गया कि हिन्दुस्तान में ऐसे कुछ ब्रैंड नेम्स चल रहे हैं—करीब करीब 37 ब्रैंड ऐसे हैं जिन का जीवनदायिनी औषधियों से कोई रिश्ता नहीं है, उन के इस्तेमाल से शरीर में जहर ही फैलता है और उन में 16 ऐसी हैं, जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन में कबूल भी किया है कि जो मनुष्य के लिये घातक हैं लेकिन आज तक उन पर रोक नहीं लगी तो मैं जानना चाहता हूं कि यह रोक क्यों नहीं लगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस रोक न लगने के पीछे कुछ कारण अवश्य हैं। मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करता लेकिन ऐसा जरूर है कि इस के पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। खैर, इस को छोड़िये। यह भी कहा गया कि सरकार ने फैसला किया है कि इन 117 ब्रैंड नेम्स में से केवल 5 नाम ऐसे हैं—अनलजीन, ऐस्पीरीन, फेरम सल्फेट, क्लोरोप्रामोमीन और पाईरैरीजीन साल्ट, इनके व्यावसायिक नाम हटाने का फैसला सरकार ने किया है लेकिन कड़े विरोध के कारण आज तक इस दिशा में कुछ नहीं हो पाया और इस फैसले को अमल में नहीं लाया जा सका और जब ऐसा होता है तो शक करना पड़ता है कि इन मगरमच्छों की इतनी ज्यादा बड़े लोगों के बीच में घुसपैठ है, राज्य व्यवस्था चलाने वालों के बीच में इतनी पहुंच है कि कोई उन का बालबांका नहीं कर पाता। कोई विदेशी कम्पनी हो उस को जो लाइसेंस मिला हुआ है वह उस से ज्यादा दवाई बनाये, जिस चीज का लाइसेंस मिला हुआ है उस को बनाये या न बनाये या उस के अलावा कोई दूसरी चीज बनाये, उस में उस को कोई रोकटोक नहीं है। आज हालत यह है कि जिस चीज का लाइसेंस उन को मिलता है उस के लिये जो दवाइयां उन को इंपोर्ट

करनी है उन की कस्टम डिपार्टमेंट के पास कोई सूचना नहीं होती। यह कम्पनी खाली नाम लिख देती है। क्या सरकार यह नहीं कर सकती कि जो लाइसेंस दिया जाता है उस की फोटोस्टेट कापी हो या ओरिजिनल आर्डर हो वह माल के साथ रहे ताकि अगर कोई आफिसर उसे देखना चाहत है तो वह देख सके। यह बेसिक ड्रगों के साथ हो सकता है। और इसी के साथ दूसरी बड़ी बेईमानी आज चल रही है एक बल्क ड्रग के नाम पर और दूसरी फार्मलेशन के नाम पर। बल्क ड्रग के इम्पोर्ट की बात तो मैं मान सकता हूं कि उसको मंगाने की जरूरत हो तो मंगाना चाहिये। यह हैरत की बात है कि उसको छोड़ कर फार्मलेशन बनाने वाले के मामले पर, नुस्खा बनाने वाले मामले पर एकाधिकार करके ये कम्पनियां अपना व्यापार चलाती हैं। क्या सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती? हिन्दुस्तान में हम लोग इतने बदकिस्मत हैं कि हिन्दुस्तान के 50 लाख बच्चे सिर्फ पेट की बीमारी से पीड़ित हैं क्योंकि पीने को शुद्ध पानी नहीं मिलता। दूसरे उनको चाइल्ड डाइरिया हो जाता है। उससे वे मर जाते हैं। टी. बी. से 50 लाख लोग मरते हैं। कोढ़ का तो व्यापक प्रसार हो रहा है। बोढ़ इस देश में बढ़ रहा है। सरकारी कोढ़ बढ़े, भ्रष्टाचार का कोढ़ बढ़े तो वह बढ़ेगा लेकिन शरीर के साथ जो बोढ़ जुड़ जाता है तो कुछ न कुछ कहना पड़ता है। उसके लिये कहना पड़ता है कि कोई इलाज करिये। आज तक कोई गरीब आदमी कोढ़ का शिकार नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 900 करोड़ रुपये की दवाइयां आयात होती हैं उनमें से मुश्किल से 14 परसेंट जीवनदान औषधियों के लिए हैं। इन दवाओं के लिये अगर उनको लाइसेंस मिलता भी है तो

वे उनको बनाना नहीं चाहेंगे। जैसा मैंने कहा कि शरबत बनाते हैं, दूसरी दवाएं बनाते हैं, टॉनिक बनाते हैं, विटामिन जिनमें होता है वे दवाइयां बनाते हैं। बाहर के विटामिन से हिन्दुस्तान बनाया जा रहा है। इसमें मसला हल नहीं हो सकता। इसलिये मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार का एक निश्चित नीति घोषित करनी चाहिये। मैं इस राय का हूं कि हिन्दुस्तान में जो भी आयातित दवाओं की जरूरत पड़े सरकार को ईमानदाराना तरीके से घोषणा करनी चाहिये कि वह सिर्फ सरकारी कारखानों में आयेगी। इस पर एक नया मामला खड़ा कर देते हैं कि इस पर एक हाई पावर टेक्नीकल कमेटी बैठायेंगे। इसमें कौन से टेक्नीकल ज्ञान की जरूरत है मुझे समझ नहीं आता। इसमें कौन सा टेक्नीकल ज्ञान लगता है। एम्परीन और दर्दनाशक दवाएं अलग-अलग कम्पनियां बनाती चली जा रही हैं। हालात यह है कि जितने का उनको लाइसेंस दिया गया है उससे ज्यादा वे बनाती चली जाती हैं। टनों के हिसाब से वे गोलियां बनाती हैं। पैसे, डेढ़ पैसे की गोली उनको पड़ती है जबकि बाजार में 15 पैसे की बिकती है। जीवनदानी औषधियों के मामले में आपको कोई नियम बनाना होगा। क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है कि जिस औषधि का जो लागत मूल्य है उससे ज्यादा, डबोडे मूल्य पर नहीं बिकेगी? स्ट्रेप्टोमाइसीन, पेंसलीन, टेटरासाइक्लीन जो ये दवाइयां हैं इन पर जो लागत खर्च आता है उससे ज्यादा ये बाजार में नहीं बिकेंगी, सरकार को इस बारे में निश्चित नीति बनानी चाहिये। सरकार ऐसी योजना बनाए, कोई ऐसी नीति निर्धारित करे कि जो दवाएं हिन्दुस्तान में आयेंगी उसे सरकार एस.टी.सी. के मातहत मंगायेगी?

[श्री लाइलो मोहा निगम]

किसी देशी, विदेशी कम्पनी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह सीधा मंगाये। सरकार से लेकर अगर वह अपनी फैक्टरी चलाना चाहे तो चलाये लेकिन उसमें भी बदमाशी है। 14 सौ, 15 सौ, रुपये किलो की दवाएं बाजार में 30-35 हजार रुपये किलो तक बिकती हैं। इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा है। इस इम्पोर्ट को आप रोक नहीं सकते हैं। बार-बार यह सवाल आ जाता है लेकिन कुछ नहीं होता। उस रोज भी मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि यह सवाल तो कूद-कूद कर आ जाता है लेकिन इससे संबंधित जो दूसरे सवाल होते हैं वे नहीं आते हैं। उसके पीछे कोई न कोई घोटाला जरूर लगता है। मैं बहुत अदब से निवेदन करना चाहूंगा कि दो-चार चीजों का निश्चित घोषणा इनको करनी चाहिये। जो भी दवाएं देश में बाहर से आयात की जायेंगी वे सरकार खुद खरीदेगी। दूसरे उन आयातित दवाओं से फार्मुलेशन को स्पेसिफिकेशन बना देना चाहिये।

हिन्दुस्तान में जो 15 हजार किस्म की दवाइयां हैं उन को घटाकर सरकार दो तीन हजार तक कर सकती है। बल्कि यहां तक कहा गया है कि चार पांच सौ किस्म की दवाइयों से भी काम चल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हिन्दुस्तान को सिर्फ दो सौ किस्म की दवाइयां जरूरत है और उससे हिन्दुस्तान की 90 प्रतिशत बीमारियां का हल निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में मेरी समझ में नहीं आता कि हिन्दुस्तान के इस मंत्रालय में बैठकर वि. व. स्वास्थ्य संगठन के अफसरों से ज्यादा दिमाग कोन रखता है। हाथी कमेटी ने तो 40 दवाइयों तक की बात कही है। लेकिन आप कम्पनियों को 15 सौ दवाइयां बनाने की इजाजत देते जा रहे हैं

इस लिये मेरा निवेदन है कि आपको इस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के घोटालों पर ध्यान देना चाहिए आप इस ओ. जी. एल. के सिस्टम को बन्द करें। जो भी इम्पोर्ट करना हो, सरकार खुद करे। देशी विदेशी कम्पनियों से लेकर। हिन्दुस्तान में दवाइयों के दामों पर भी आपको कोई न कोई निश्चित नीति घोषित करनी चाहिए। सरकार से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सन 1974 में बनी हुई हाथी कमेटी की रपट आज तक देश की जनता के सामने क्यों नहीं खोली गई? देश की जनता के सामने इस रपट को रखने में क्या अड़चन है? अखबारों में जो कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है उस से हम लोगो को कुछ मालूम हो जाता है। उपसभाध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस मामले पर आये घंटे की बहस उठाने का मौका दिया। और भी कई चीजें हमारे मित्त कहेंगे, लेकिन मैं इतना ही चाहता हूं कि इस मामले में सरकार को अपनी पूरी नीति घोषित करनी चाहिए। जहां तक विदेशी कम्पनियों के इनव्रीटी शेयर्स का ताल्लुक है, उनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हाथ कमीशन ने जो यह कहा है कि तत्काल इसी क्षण किसी विदेशी कम्पनी के शेयर्स 40 प्रतिशत नहीं हैं तो उन को 26 प्रतिशत कर देना चाहिए और इस पर कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि बहु-राष्ट्रीय कंपनियां अगर अपना शेयर नहीं करती हैं और जो उनको लाइसेंस दिया गया है उसका उल्लंघन करती हैं और जो माल आयात किया जाता है उसका दुरुपयोग करती हैं तो उनके लाइसेंस जब्त कर दिये जायें और ऐसी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। जो विदेशी दवाइयां हमारे देश में आयें उनका सिर्फ इस्तेमाल सरकारी उद्योगों के जरिये से

होना चाहिए । यही मेरा निवेदन है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय लाडली मोहन निगम ने जो प्रश्न उठाये हैं और मेरा ऐसा ख्याल है कि अपना भाषण करते हुए उन्होंने जो प्रश्न उठाये हैं उनको उठाते समय उन्होंने मूल प्रश्न को देखने की तकलीफ नहीं की है । यह प्रश्न जो सदन के सामने विचाराधीन है वह केवल एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है और वह स्टार्ड क्वेश्चन नं० 223 रिगाडिंग कस्टम्स क्लियरेंस फार इम्पोर्ट आफ इंग इन्टरमिडियेट्स अन्डर ओ० जी० एल० से संबंधित है । इस में जो चर्चा का विषय है वह केवल कस्टम्स क्लियरेंस के बारे में ग्लेस्को कम्पनी के बारे में जो अनेक प्रश्न इस सदन में और दूसरे सदन में उठाये गये हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं । लेकिन श्री लाडली मोहन निगम ने इस प्रश्न से संबंधित पृष्ठभूमि बताते हुए राष्ट्रीयता, उपचार, बीमारी, दवाइयों के मूल्य और केन्द्रीय शासन की उस संबंध में नीति संबंधी प्रश्न भी उठा दिये जिन का कि जो विषय सदन के सामने विचाराधीन है उस से दूर का भी संबंध नहीं है । (व्यवधान) आप मेहरबानी करके बैठ जाइये । जब आपकी टर्न आये तब बोलिये । मेरा निवेदन है कि उन्होंने जो बातें उठाई हैं उनमें चार बातें उठाई हैं और उनका इस विचाराधीन विषय से संबंध नहीं है । अपने भाषण के आखिर में उन्होंने पूछा है (व्यवधान) ।

श्री लाडली मोहन निगम : यह इम्पोर्ट का मामला है ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : उन्होंने चार प्रश्न उठाये हैं । एक तो उन्होंने कहा कि दवाइयां सरकार खुद आयात

करे । दूसरा स्पेसिफिकेशन तय कर देने चाहिए । तीसरा ओ० जी० एल० को बन्द करना चाहिए । और चौथा हाथी कमैटी की जो रिपोर्ट सन् 1974 में प्रस्तुत हुई थी उस के बारे में शासन क्यों निर्णय नहीं लेता है । मेरा निवेदन है कि जहां तक फाइनेंस मिनिस्ट्री का संबंध है उसको इन चारों प्रश्नों का उत्तर देने में इसलिये मजबूरी है कि असली प्रश्न कस्टम क्लियरेंस के बारे में है । इस प्रश्न से संबंधित अगर प्रश्न किये गये होते तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उनका उत्तर देती । लेकिन लगता है कि श्री लाडली मोहन निगम ने उनसे संबंधित जानकारी लेने की आवश्यकता महसूस नहीं की है ।

इसलिए मैं उसका उत्तर देने में मजबूर हूं । यह जो सवाल है, यह जो प्रश्न है, यह बड़ी व्यापक चर्चा का विषय है और इससे केवल कस्टम डिपार्टमेंट ही संबंधित नहीं है बल्कि डिपार्टमेंट आफ कैमिकल एंड फर्टिलाइजर, डाइरेक्टर जनरल टेक्निकल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्रीज, चीफ कन्ट्रोलर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट और मिनिस्ट्री आफ ला एंड जस्टिस एंड कम्पनी एफियर्स, इन तमाम विषयों से इसका संबंध है । जहां तक कस्टम का संबंध है, माननीय श्री लाडली मोहन निगम ने कस्टम क्लियरेंस के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं । दूसरे प्रश्न जो किये गये हैं, उससे इसका संबंध नहीं है, इसलिये मैं इसका जवाब देने के लिये मजबूर नहीं हूं ।

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA (Maharashtra): Sir, our hon. Minister has stated specifically that he can only answer questions in regard to customs and Messrs. Glaxo. I would like to be very specific about it. He has

[Dr. Smt. Najma Heptulla]
solved a lot of problem. Messrs. Glaxo have imported Triene, Beta-methyl Preg and other inter-mediate, penultimates for manufacture of Betamethasone and its salts. I have to take all these names, the names of all these chemicals. This may not come under his Ministry. But these are the drugs which have been imported.

Sir, according to the industrial licence granted to Messrs. Glaxo, it does not permit any foreign exchange utilisation to this activity. According to the Import Trade Control Policy and customs public notice, the unit has to satisfy the customs authorities. They are allowed to import the material according to the industrial licence and the unit has to furnish a declaration providing all the information concerning permission number and the end product for which the material is to be used. My question is, how these have been allowed clearance? This is a very specific question for the customs and this is against our policy and rules laid down by the Import Control Policy for April, 1980-81.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : श्रीमन्, मेरा पहला सवाल है जो इनके मंत्रालय से संबंधित है, जिसको ये चाहते हैं कि हमारे मंत्रालय से संबंधित हो ।

विदेशी कम्पनियां हैं, ड्रग कम्पनियां हैं उनकी एक्टिविटी कैपिटल को घटाने के लिये कि 40 प्रतिशत वह करें, क्या इस तरह का आदेश आपने दिया है और इन कम्पनियों ने क्या उसको कम्पलाई किया है और अगर नहीं किया है तो किन कम्पनियों ने कम्पलाई नहीं किया है ? जिन्होंने नहीं किया है उनके खिलाफ आप कौन सी कार्यवाही कर रहे हैं ?

दूसरा सवाल यह है कि विदेशी कम्पनियां, ड्रग कम्पनियां जो हैं प्रति साल कितना मुनाफा बाहर भेजती हैं। पर इयर 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा भेजती हैं। आप ठीक-ठीक बता दें कि कितना मुनाफा भारत से बाहर ये कम्पनियां भेजती हैं ?

तीसरा सवाल, हो सकता है कि यह प्रश्न थोड़ा बाहर जाये। लेकिन जिन दवाइयों के एक्सपेरिमेंट ड्रग कम्पनियां, विदेशी या देशी कर रही हैं तो स्नेक ब्वाइट जैसे हैं क्या इसके लिये कोई दवा बनाई जा रही है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): How do you expect the Finance Minister to take care of snakes?

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: He can say that this is not relevant. The matter ends there. He can give the same reply, as he has said just now in reply to the questions put by Mr. Ladli Mohan Nigam, that all these questions are irrelevant.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): You are being more irrelevant. How do snakes come into this question?

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: They are manufacturing many things. I would like to know, what medicine has been invented?

चौथा और आखिरी सवाल। देशी दवाओं के प्रगति के लिए, विकास के लिये, चाहे यूनानी हो और चाहे आयुर्वेदिक हो, छठीं योजना में आप की क्या रूप रेखा है, क्या कार्यक्रम है ?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार)
उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अभी यह बता रहे थे, विस्तार में कि श्री लाडली

मोहन निगम जी ने जो प्रश्न पूछे हैं वे प्रश्न वित्त विभाग से संबंधित नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि प्रश्न किये गये और जब उन प्रश्नों में स्पष्ट उत्तर नहीं आया, स्पष्टीकरण नहीं हुआ इसलिए मैंने पूछा कि आप यह बताये कि प्रश्न खण्ड 'क' में जिन दवाओं का जिक्र किया गया है, उन दवाओं के बारे में अभी तक आप को क्या जानकारी है और वे कितनी मात्रा में आयात की की गई है। इससे जानकारी कस्टम डिपार्टमेंट के पास नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर सरकार इसकी जानकारी रखे चाहे न रखे यह पूछा गया था कि कम्पनियों की घ.षणायें नियमानुकूल पाई गई या नहीं, सरकार का उत्तर है और मंत्री महोदय कहते हैं कि यह कहना संभव नहीं है कि किन-किन मामलों में आयात-कर्त्ताओं की घ.षणायें सही पाई गई अथवा सही नहीं पाई गई।

सरकार क्यों ग्राम है। कोई कम्पनी जब दवा मांगती है, जब आयात करती है तो उसको नियमानुसार कुछ घ.षणायें करनी पड़ती हैं, और उस घ.षणा के बारे में यह प्रश्न पूछा गया कि उनके द्वारा की गई घ.षणाएं सही थीं, गलत थीं, नियमानुकूल थी या उसमें अनियमितताएं थी। यह भी सरकार बताने में अक्षम है तो आज सरकार यह बताए कि वित्त मंत्री जी उसमें से किन-किन कम्पनियों द्वारा की गई घ.षणाएं नियमित थी और किन किन की अनियमिततायें थीं। जिन कम्पनियों की घ.षणाओं में अनियमिततायें थीं उनके विरुद्ध अब तक सरकार के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं? अंतिम सवाल मेरा यह है कि यह जो सवाल इस तरह का पूछा गया है यह सही है प्रश्न वे खण्ड (ग) में ग्लेक्सो

कम्पनी का जिक्र किया गया है उसके पहले के किसी खंड में ग्लेक्सो कम्पनी का जिक्र नहीं है अंतिम खंड में ग्लेक्सो कम्पनी का जिक्र आया है तो ग्लेक्सो कम्पनी के बारे में सवाल उठाया गया कि जिन दवाओं का आयात ग्लेक्सो कम्पनी के द्वारा किया जाता है उन्हीं दवाओं का निर्माण देशी कम्पनियों द्वारा देश में हो सकता है। देशी कम्पनियां जब दवाओं का निर्माण करती हैं तो उन्हीं दवाओं को ग्लेक्सो कम्पनी की मारफत विदेशी कम्पनियों से आयात करवाने के क्या कारण हैं? सरकार का भी जो कस्टम विभाग है उससे यह सवाल संबंधित है क्योंकि जो आयात या निर्यात किया जाता है वह पैसा वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और वित्त मंत्री इस विषय में जांच पड़ताल करते हैं या नहीं करते हैं इस मामले में वित्त मंत्री के द्वारा जांच पड़ताल की गई या नहीं की गई?

DR. JOSEPH LEON D'SOUZA (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the statement he made a little while ago that the subject matter does not come within the purview of the Customs Department only. With due apology to the hon. Minister, I would like to point out to this House that my hon. friend Mr. Ladli Mohan Nigam has asked for this Half-an-Hour discussion in response to Starred Question No. 223 very specifically and one part of that Question relates to customs. There are three parts (a), (b) and (c). Part (c) no doubt comes within the purview of the hon. Minister and his department, but that does not preclude me to make a reference to parts (a) and (b) which is also quite relevant to his department.

[Dr. Joseph Leon D'Souza]

Now, Sir, coming to the point, intermediaries are being imported into the country involving foreign exchange, which the hon. Minister will bear with me since it involves the use of foreign exchange does directly come within the purview of his department. Sir, why are these intermediaries being imported into this country? The process for the manufacture of betamethasone is in 12 stages, that is, if one produces it from the three available roots indigenously available in India. Now the licence that has been given specifically mentions that the raw material deployed in the manufacture Betamethasone shall be indigenous and the process, therefore, will be in 12 stages.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): May I draw your attention to one thing? I am not personally a doctor or a chemist or anybody...

SHRI HAREKRUSHNA MALICK (Orissa): You are the esteemed Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): The way in which you are asking the question, the parameters of the question relate to customs clearance and the hon. Minister will not be able to throw light on any of your points. Please confine yourself to the parameters of this question.

DR. JOSEPH LEON D'SOUZA: No, Sir, it is for the definite edification of the hon. Minister that I am drawing my inference before I ask the question because the intermediates are being imported in the country involving foreign exchange which is directly within the purview of his Ministry. Sir, I am not departing from the point. I have heard the hon. Minister very clearly. What pertains to his Department in a

preamble I have to ask him. Once he is convinced—in fact he is not only convinced but Government of India is aware of the fact that intermediates are being imported into this country—and may I make a reference to the affidavit filed by the Government of India in the Delhi High Court where in the case of Glaxo Company they have admitted that they are aware of the fact that these are being imported? So that is established, Sir.

If they were imported, which are not permitted to be imported, then this is my question. To release this material, there is a special procedure. In a Government Notification issued by the Government, the special procedure has been well defined that it is mandatory on the part of the company which imports these to give photostat copies of permission granted—Sir, I am specific on the subject—for the import clearance of that material, clearly specifying what use it will be put to as far as the end product is concerned. It has got to be mentioned that Triene is being imported against foreign exchange for the manufacture of Betamethasone. It is not sufficient—it is for the hon. Minister to understand—and which is clandestinely being done by the companies—to merely mention that they are registered under the DGTD and not mentioning any permission, not giving photostat copies and not indicating the reason for the import of this against the end product. This is my point, Sir. The procedure of the Government is crystal clear; no question about that. But the execution of it at the level of the Customs, where this point is overlooked while scrutinising the consignment to be cleared, is the lacuna, to which I would like to draw the attention of the hon.

Minister. If this is done, that will avoid all difficulties.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maha ashtra): This Question arises out of Unstarred Question No. 2690, asked earlier.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): It is Starred Question No. 223.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Sir, the main question is . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): No, no, I am not concerned with the main question. It must concern the Question under discussion today.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Sir, the Question itself arose with reference to Unstarred Question No. 2690 dated 22nd December, 1981. Otherwise I would not have referred to it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): All right, go ahead. Ask your question.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: But you do not allow me to speak. What can I do?

The Question was:

"Whether it is a fact that Glaxo company have imported large quantities of Triene, Beta Methyl Preg epoxide and 16-DPA required for the production of Betamethasone by giving wrong declaration to customs authorities;"

And the reply was very interesting:

"Since Party-wise records of imports are not maintained by the Customs authorities, it is not possible to furnish the required information".

The second question was:

"whether it is also a fact that the procedure of giving declaration came in vogue only after the OGL policy;"

And the answer was: "Yes, Sir." And what is the policy?

They have to give a declaration at the Customs that these are the imported drugs as per the prescribed regulations and as given in the Import Policy which has been declared by the Government. That Policy says that those companies must publish annually details of import of each material that together account for a major proportion of the total imports. That declaration has to be given at the Customs itself. May I know from the Minister whether the Glaxo Company's declarations for import clearance were not in order, were against the rules? And this has been done by other companies also. Therefore, there is a collusion between the Customs authorities and the importing companies. May I know from the Minister the steps he is taking so that this sort of collusion between the foreign companies and the Customs authorities is avoided; and how many cases of false declarations he has detected?

SHRI HAREKRUSHNA MALICK: Sir, the first point I want to make clear and emphasise is that the Ministry of Finance is the key Ministry to regulate our export and import. Therefore, anything that is not necessary to be imported is to be screened there. There is no such Ministry as the Ministry of Customs; it is only a portion in the Ministry of Finance. Therefore, the hon. Minister should take note of it that the entire thing comes under his purview and there is joint responsibility, whatever Ministry or Department may be concerned. He must convince all of them

[Shri Harekrushna Mallick]

that the right step is taken. No matter what has happened so far, from today just have a new stand and take a stand *de novo*. I am to inform the esteemed House that our own firm, IDPL, in 1978 charged and as much as Rs. 4 crores worth of antibiotics went stray because there is also a collusion in our country between different Departments. These departments do not accept consignments from them. Not only that. In Madras, they are running a factory. Their product is not being utilised. So there is collusion between different departments to see that they carry on this import and make a mischief and make money. Therefore, the hon. Minister should see that all these consignments are held up, no clearance is given until we supervise that actually such a thing is a new thing, it is not found in the country; nor can it be made in the country. Then only the clearance should be given. (*Time-bell rings*).

Just one example I am giving. Cartisan is a basic chemical which has so many names. These names vary from A to Z. Why should we allow these things from A to Z to be imported? Similarly, in antibiotics penicillin is the basic drug. Now we have ampicillin and so many other names. One constraint is marketing. The same thing comes in the market in different names with different labels through small agencies, cooked up. They are just like cancer. The position is like that of cancer everywhere. Therefore, these multi-nationals are progressing like cancer patches with different loopholes. We should see that these loopholes are plugged. IDPL is competent enough to cater to the needs of the country. It should be augmented and all concerns of the Government should see that they give in kind.

When we give money for Orissa or Madhya Pradesh, we say Rs. one crore or Rs. ten crores. It must go in kind from IDPL, so that you really plug the loopholes. I want an answer from the Minister.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: How can he give the answer?

PROF. (SHRIMATI) ASIMA CHATTERJEE (Nominated): Mr. Vice-Chairman, I would like to say a few words in connection with the import of drug intermediates by some foreign companies. What they actually do while submitting applications for the import of drug intermediates is that they actually state that these intermediates are not available in the country and they are going to import and finally by several chemical reactions they are going to produce the valuable drugs, may be life saving or common drugs. But in some cases it has been observed that actually they almost bring the finished products. Instead of several reactions, either by half a reaction or a single reaction, they convert the material into finished products and thereby they sort of hoodwink the Government. But it is very difficult for the Government also to realise this. I have one suggestion because I was also a member of the Drug Inquiry Commission of West Bengal, of which Mr. Biren was the Chairman, in 1974. So I know all these details. That is why I would like to suggest that when they submit the applications they must be specific as to what actually are the drug intermediates. In how many States they are going to apply and how many States they are going to apply for the finished products? If they fail to supply this data and if they do not obey the instructions in this respect, I think it will be very difficult for our Indian firms to compete with

them. It is my humble suggestion which I would like to make for the consideration of the hon. Minister.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: Sir, as many as 7 hon. Members have taken part in this discussion and they have raised very valuable points and made good suggestions. It is very good that in this discussion, 4 doctors have taken part although some of them may be doctors of literature.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: All of them are medical doctors.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: They have taken part and it was expected of them that they will make very good suggestions. I am sorry that Dr. D'Souza and others have not taken care to see carefully the subject under consideration before the House. My friend, Mr. Lalli Mohan Nigam raised only two points coming out of the Starred Question No. 223 and the two points are whether there has been any violation of various legal provisions by the Executive Directors of Glaxo Company and secondly, why there has been so much delay in taking action in the matter. You will not kindly expect me and my colleague, Shri Dalbir Singh, State Minister for Petroleum, Chemicals and Fertilizers, to enter into a discussion. It will not be proper and also the rules and procedures do not allow that I should give a reply to those questions which are not relevant to the specific points raised by Shri Lalli Mohan Nigam. (Interruptions)

SHRI JOSEPH LEON D'SOUZA: Sir, he has not answered my questions.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: As far as Shri Shiva Chandra Jha, Shri Yadav and Shri Dhabe are concerned, they have

mainly raised questions of policy as to what should be the method of import and export and what should be the policy of the Government regarding several other matters connected with the subject. The specific question before the House as I have mentioned just now . . .

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Would the hon. Members please take their seats? I will take care of it. I have heard everybody. I will try to find out what he has to say. You don't worry. I am here to protect the interests of the Members.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Shri Dhabe raised the question of collusion between the multi-nationals and the customs authorities. What is your reply to that?

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: Please try to hear me if you have got any patience. You will hear the reply.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: I have got enough.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: As far as Dr. Najma Heptulla is concerned, she raised very valid points regarding this and I want to make the position clear. For clearance of imported goods under OGL, the importers are required to file documents with the Customs (Bill of Entry) indicating that the importation is sought clearance under OGL. To this effect a specific declaration is also given by the importers as required under Para 13 of App. 10 of the Import Policy concerning the conditions governing OGL. Accordingly, in respect of their imports, M/S Glaxo have been giving declarations. While assessing the goods to duty, customs authorities at the ports allow the clearance under OGL if the same do not figure in the category of banned restricted, canalised items, etc. Besides accepting

[Shri Sawai Singh Sisodia]

the declarations given by the importers, customs authorities also verify whether item imported is the raw material for the manufacture of end-product for which importers hold industrial licence. In case of M/S Glaxo, they had licence for the manufacture of Betamethasone for which they are reported to have imported the drug intermediates. Thus, on the basis of their declaration and the industrial licence, in so far as customs laws are concerned, there has been no violation. However, the issue as to whether M/S Glaxo have violated any provision of the Industrial Licence, is still under consideration by the Department of Chemicals and Fertilisers. In case it is established that there has been any violation, concerned Departments would certainly examine regarding taking appropriate action under the concerned laws.

It has been just mentioned by Dr. D'Souza that the matter has been taken before the High Court in June 1981. M/S Glaxo filed a writ petition. Then it was found that there were some irregularities and in this connection enquiries were made and the opinion of the Law Ministry was obtained. The Law Ministry's advice was received in February 1982. The Law Ministry have advised that there is no condition prohibiting import of Triene as such for production of Betamethasone by the company in the licence issued in 1964 and hence it is not established that any condition of licence has been violated. They have further advised that it may be legally difficult to bring the case of violation of the conditions of such a licence. But this matter is under the consideration of the Department of Chemicals and Fertilisers. They have not taken any final stand or action in the matter. It is still under their consideration. Therefore, the question specifically raised as to whether there is any violation has

been answered. The other question was why there has been delay in taking action. The matter has come to the notice of the Department in 1981 and in 1982 the Law Ministry's advice was obtained and further action is under consideration. Therefore, there is no delay also on the part of the Department.

The declaration that they are registered with the DGTI has been found to be in order. This question was also raised. The question that they are actual users of imported drug intermediates in accordance with the conditions of licence is under examination of the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilisers. M/S Glaxo has been asked to reduce their equity to 40 per cent. Details of profit remittances are not available.

These are the questions, points and suggestions and observations made by the hon. Members just now.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: On a point of order. These are the materials supplied by the Ministry through an answer to question No. 308. It says that these people have got licence to manufacture Betamethasone under Licence No. L/22/236. They have been licensed to manufacture this drug not only with indigenous technology, but with indigenous material. They are not supposed to import this drug or any part of it or component. They have been violating this rule and under the pretext of OGL they are importing raw materials which are required for manufacturing this. Dr. Ashima Chatterjee and Dr. D'Souza also mentioned this. The process of manufacturing the final drug is taken into account for purposes of decision on equity as to how much equity a foreign company will have. They are importing this final drug. Sir, they are violating not one rule, but a number of rules. And the

Minister says, there is no...
(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I will summarise what you all want to say. (Interruptions)

SHRI JOSEPH LEON D'SOUZA: I am on a point of explanation. The hon. Minister has made a statement, quoting the Law Ministry, that this is in order. Sir, the final point of this has got to be understood. Nobody said that they should not import under Open Licence. Nobody said so. (Interruptions) I hope the hon. Minister is listening to me. But the licence issued is under a specific condition that indigenous material will be used or shall be used and 'you shall not import any material which will involve foreign exchange; you can do so if it does not involve any foreign exchange'. So it is a violation of the contract. When it involves foreign exchange, can the hon. Minister be oblivious of the fact that the National Exchequer is being deprived of a legitimate....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I understand it. Mr. Minister, do you want to say something? (Interruption.)

PROF. (SHRIMATI) ASIMA CHATTERJEE: These cannot be imported, provided these chemicals and materials are available in this country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): That point has been made already.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA And this is the answer given.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I know, Madam.

SHRI SAWAI SINGH SISO-DIA: I have simply mentioned what is the position on this issue before the Ministry of Chemicals and Fertilizers. They have referred this matter for advice to the Law Ministry. I have read the opinion of the Law Ministry. But I have also stated that the issue as to whether GLAXO have violated any provision of the industrial licence is still under consideration of the Department of Chemicals and Fertilizers, and that is the competent administrative Ministry. It will decide what action should be taken. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Minister, I have heard all the Members. (Interruptions) For Heaven's sake, please sit down and try to understand it. I have heard the Members as well as your reply. In the last session we discussed this. Mr. Minister, I do not want to say something which is embarrassing to the Government. But the point seems to be that Members are not happy at all. Whatever decision you want to take, it seems that there is a flagrant violation by GLAXO Company under the Customs Rules also, and you are well advised to take care and place this information before this House in the next session. (Interruptions) Thank you.

Now, the House is adjourned till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at fifty-four minutes past six of the clock till eleven of the clock on Friday, the 26th March, 1982.